

भारतीय रेलवे की राजस्व समस्याएँ

प्रलिमि्स के लिये:

भारतीय रेलवे (IR), पूंजीगत व्यय (capex), सकल बजटीय सहायता (GBS), अतरिकित बजटीय संसाधन (EBS), भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (CAG), नेट टन किलोमीटर (NTKM), परिचालन अनुपात ।

मेन्स के लिये:

आर्थिक वृद्धि और विकास में भारतीय रेलवे की महत्त्वपूर्ण भूमिका एवं योगदान।

स्रोत: द हिंदू

चर्चा में क्यों?

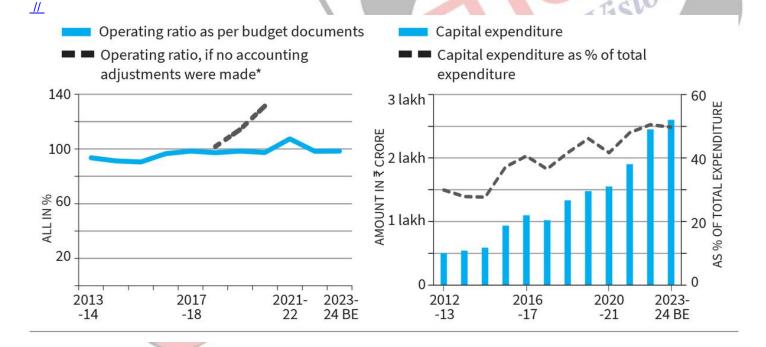
भारतीय रेलवे (IR) ने अपने रेल बजट को मुख्य बजट में विलय करने के बाद से अपने पूंजीगत व्यय (कैपेक्स) में उल्लेखनीय वृद्धि की है। हालाँकि इसका परिचालन अनुपात, जो राजस्व के वरिद्ध व्यय का मापन करता है, में संशोधन नहीं हुआ है।

भारतीय रेलवे की वर्तमान चिताएँ:

- ऋण जाल की चिताएँ:
 - भारतीय रेलवे (IR) बढ़ते कर्ज़ से संबंधित समस्या का सामना कर रहा है। अधिशष निधि के अभाव में भारतीय रेलवे सकल बजटीय सहायता (GBS) और <u>अंतरिकित बजटीय संसाधन (EBS)</u> के माध्यम से बढ़ी हुई निधि पर निर्भर रहा है।
 - हालाँक EBS पर यह निर्भरता एक महत्त्वपूर्ण लागत के साथ आती है । मूलधन और ब्याज के पुनर्भुगतान पर भारतीय रेलवे का खर्च राजस्व प्राप्तियों का 17% है, जिसने सत्र 2015-16 तक 10% से भी कम वृद्धि की है ।
- अनुत्पादक नविश की तुलना में आर्थिक विकास से संबंधित चिताएँ:
 - ॰ बढ़ते कर्ज़ के बावजूद भी पूंजीगत व्यय में उल्लेखनीय वृद्धि इस विश्वास पर आधारित है कि रेलवे क्षेत्र में नविश का विनिर्माण, सेवाओं, सरकारी कर राजसव और रोज़गार के अवसरों पर सकारात्मक प्रभाव पढ़ रहा है।
 - हालाँकि यह ज़रूरी है कि भार<mark>तीय रेलवे</mark> एक महत्त्वपूर्ण संगठन के रूप में एयर इंडिया जैसी संस्थाओं में देखी जाने वाली वित्तीय अस्थिरिता से बचने पर ध्यान केंद्रति करे।
- घटते शेयर:
 - ॰ **पछिले कुछ वर्षों में प्रमुख वस्तुओं के परविहन में अपनी हसि्सेदारी** घटने के कारण भारतीय रेलवे (IR) को एक महत्त्वपूर्ण चुनौती का सामना करना पड़ रहा है।
 - उदाहरण के लिये, **वर्ष 2011 में** कोयला परविहन 602 मिलियन टन (MT) था, जिसमें रेलवे हिस्सेदारी 70% थी, लेकिन वर्ष 2020 तक कोयले की खपत बढ़कर 978 मिलियन टन हो गई, जबकि रेलवे हिस्सेदारी घटकर 60% रह गई।
 - इसी तरह बंदरगाहों से आने-जाने वाले एक्ज़िम (निर्यात-आयात) कंटेनरों की हिस्सेदारी में वर्ष 2009-10 के बाद से 10 से 18% के बीच उतार-चढ़ाव आया है, वर्ष 2021-22 में4 यह आँकड़ा 13% है।
- नविल टन कलोमीटर (NTKM) से संबंधति चताएँ:
 - वर्ष 2015-16 और 2016-17 में NTKM में क्रमशः 4% तथा 5% की अभूतपूर्व गरीवट दर्ज की गई।
 - वर्ष 2021-22 में समाप्त होने वाली सात वर्ष की अवधि में NTKM ने 3.5% की वार्षिक वृद्धि दर दिखाई, जो सड़क परविहन में वृद्धि दर से काफी कम है।

भारतीय रेलवे प्रणाली में दीर्घकालिक मुद्दे:

- वित्तीय प्रदर्शन में चुनौतियाँ:
 - भारतीय रेलवें को अपने वित्तीय प्रदर्शन के साथ एक समस्या का सामना करना पड़ रहा है, विशेष रूप से इसके लाभदायक माल खंड और घाटे में चल रहे यात्री खंड के बीच काफी अंतर है।
 - भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) की वर्ष 2023 की रिपोर्ट में यात्री सेवाओं में 68,269 करोड़ रुपए के भारी नुकसान पर प्रकाश डाला गया, जिसे माल ढुलाई से होने वाले मुनाफे से कवर किया जाना था।
- माल ढुलाई व्यवसाय में चुनौतियाँ:
 - ॰ अप्रैल से जुलाई 2023 तक माल ढुलाई की मात्रा और राजस्व में वार्षिक वृद्धि क्रमशः 1% तथा 3% रही, जबकि भारतीय अरथवयवसथा 7% की दर से बढ़ रही है।
 - भारत के माल दुलाई कारोबार में भारतीय रेलवे की मॉडल हिस्सेदारी अत्यधिक कमी के साथ लगभग 27% रह गई है, जो कि भारत की आज़ादी के समय 80% से अधिक थी।
- कार्गो का कृत्रिम विभाजन:
 - ॰ माल और पार्सल में कार्गो का कृत्रमि विभाजन दक्षता में बाधा डाल रहा है। टैरिफ नियमों, हैंडलिंग प्रक्रियाओं और निगरानी प्रथाओं द्वारा संचालित ये प्रभाग शपिर्स की चिताओं से समानता नहीं रखते हैं।
 - IR के लिये यह आवश्यक है कि वह इस कृत्रिम विभाजन को छोड़ दे और कार्गो को उसकी विशेषताओं के आधार पर थोक या गैर-थोक के रूप में वर्गीकृत करें, जिसे मूल्य-वर्धित कहा जा सकता है।
- सड़क परविहन से प्रतिस्पर्धा में चुनौतियाँ:
 - भारतीय रेलवे को सड़क परविहन से भी प्रतिस्पर्द्धा का सामना करना पड़ता है, जो रेल परविहन की तुलना में तेज़ी से बढ़ रहा है **मविल टन** किलोमीटर (NTKM) में उतार-चढ़ाव के साथ इस प्रतिस्पर्धा ने IR के लिये माल परविहन में अपनी हिस्सेदारी को बनाए रखना और विस्तारित करना चुनौतीपुर्ण बना दिया है, इसलिये रेलवे परविहन में सुधार की आवश्यकता है।
- कंटेनरीकरण की अपर्याप्तता:
 - ॰ निजीकरण के 15 वर्षों के बाद कंटेनरीकृत घरेलू माल भारतीय रेल की कुल लोडिंग का केवल 1% और देश के कुल माल का 0.3% है।
 - उच्च ढुलाई दर और संभावित नुकसान के साथ बाज़ार विकास का जोखिम इस खराब प्रदर्शन में योगदान दे रहा है।



भारतीय रेलवे द्वारा माल वहन को आसान एवं बेहतर बनाने के उपाय:

- पार्सल ट्रेनों को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने की आवश्यकता:
 - भारतीय रेलवे को पार्**सल ट्रेनों और विशेष भारी पार्**सल वैन (VPH) ट्<mark>रेनों का उपयोग करके सामान्य माल ले जाने में चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।</mark>
 - इन चुनौतियों का एक प्रमुख कारण **उच्च सीमा शुल्क** है, जो अक्सर ट्रक सीमा शुल्क दरों से अधिक होता है।
 - भारी पार्सल ढुलाई के लिये VPH पार्सल ट्रेनों को प्रतिकूल पाया गया है,कवर किये गए वैगन एक अधिक प्रभावी विकल्प हैं जो VPH पार्सल ट्रेनों की तुलना में अधिक माल वहन कर सकते हैं।
- जहाज़ कंपनियों के लिये लचीलेपन की आवश्यकता:

- भारतीय रेलवे के लिय एक बड़ी समस्या यह है कशिपिर्स को माल दुलाई सीमा शुल्क अथवा पार्सल सीमा शुल्क के तहत न्यूनतम कुछ हज़ार टन माल ही भेजना होता है जिससे यह सामान्य माल की ज़रूरतों के लिये अनुपयुक्त हो जाता है।
 - शपिर्स को अधिक लचीले और उपयुक्त विकल्प की आवश्यकता होती है जो उनके माल क्षमता के उपयुक्त हो, जैसे किसी यात्री ट्रेन में बर्थ बुक करने से पहले यात्रियों को बहुत सारे यात्रियों के साथ आने पर छूट प्रदान करना।
- माल वहन में चुनौतियों पर काबू पाना:
 - थोक माल में भारतीय रेलवे **की घटती हसि्सेदारी आंशकि रूप से रेलवे साइडिंग की उच्च लागत और पूंजी-गहन प्रकृति के कारण** है, जो छोटे उदयोगों को उनका उपयोग करने से हतोतुसाहति करती है।
 - इसके समाधान के लिये विशेषकर खनन समूहों, औद्योगिक क्षेत्रों और बड़े शहरों में**माल एकत्रीकरण एवं वितरण बिदुओं पर** आम-उपयोगकर्ता सुविधाओं की आवश्यकता है।
- रेल और सड़क द्वारा माल वहन के बीच समान अवसर सुनिश्चित करना:
 - ॰ रेल लोडंगि/अनलोडिंग सुविधाओं के लिये पर्यावरण मंज़ूरी अनिवार्य कर दी गई है, कितु सड़क लोडिंगि/अनलोडिंग सुविधाओं पर इसे लागू नहीं किया गया है। इसलिये एक समान सतत् पर्यावरणीय नियमों की आवश्यकता है।
- सीमा शुल्कों का अनुकूलन:
 - े **वॉल्यूमेट्रिक लोडिंग** को प्रोत्साहति करने के लिये लोड की गई मात्रा के आधार पर सीमा शुल्क में छूट दी जा सकती है। भारतीय रेलवे को कार्गो एग्रीगेटर्स को भी प्रोत्साहति करना चाहिये और लंबे समय में बेहतर दक्षता के लिये पेलोड एवं गति को अनुकुलति करना चाहिये।
- आधारभूत अवसंरचना का आधुनिकीकरण:
 - ें सुरक्षा, दक्षता और लागत में कमी के लिये **हाई-स्पीड रेल, स्टेशन पुनर्विकास, ट्रैक डब्लिंग, कोच नवीनीकरण, जी.पी.एस.** ट्रैकिंग तथा **डिजिटलीकरण** सहित रेलवे में बुनियादी ढाँचे के आधुनिकीकरण की तत्काल आवश्यकता है।
- परचालन लागत में कमी:
 - भारतीय रेलवे ने 98.14% का परिचालन अनुपात हासिल किया है जिसे कर्जा संरक्षण, श्रमबल को अनुकूलित करने तथा खरीद
 प्रथाओं को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करके और बेहतर बनाया जा सकता है।

थोक माल वहन क्षमता बद्राने हेतु भारतीय रेल की वभिनि्न पहलें:

- भारतीय रेलवे (IR) ने थोक माल क्षेत्र में कई पहल की हैं, जिनमेंब्लॉक रेक मूवमेंट नियमों में लचीलापन, मिनी रेक की अनुमति देना और प्राइवेट फ्रेट टर्मिनल (PFT) शुरू करना शामिल है।
- गति शक्ति टर्मिनल (GCT) नीति इन टर्मिनलों के संचालन को सरल बनाती है, इसके लिये निजी साइडिंग को GCT में परविर्तित किया जा रहा है।
- भारत सरकार ने दो प्रमुख नीतियाँ प्रस्तुत की हैं: PM गतिशक्त (PMGS) नीति, जिसका उद्देश्य एक निर्बाध मल्टी-मॉडल परविहन नेटवर्क बनाना है और राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति (NLP), जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स पोर्टल बनाने एवं विभिन्नि मंत्रालयों में प्लेटफार्मों को एकीकृत करने पर ध्यान केंद्रित करना है।
- रेलवे बुनियादी ढाँचे में निवेश: सरकार ने बंदरगाह आधारित विकास एवं सड़क विकास के लिये क्रमशः 'सागरमाला' और 'भारतमाला' जैसी योजनाएँ भी शुरू की हैं जिन्हें भारतीय रेलवे के साथ एकीकृत किया जाना चाहिये।
- डेडिकेंटेड फ्रेंट कॉरिडोर: सरकार ने 'डेडिकेंटेड फ्रेंट कॉरिडोर' जैसी योजनाएँ भी शुरू की हैं, जिनका लाभ माल परविहन को बढ़ाने के लिये उठाया जाना चाहिये।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्षों के प्रश्न:

<u>?!?!?!?!?!?!?!?</u>:

पुरश्न. भारतीय रेलवे दवारा पुरयोग किये जाने वाले जैव-शौचालयों के संदर्भ में निमनलिखति कथनों पर विचार कीजिये: (2015)

- 1. जैव-शौचालय में मानव अपशिष्ट का अपघटन एक कवक इनोकुलम द्वारा शुरू किया जाता है।
- 2. इस अपघटन में अमोनिया और जलवाष्प ही एकमात्र अंतिम उत्पाद हैं जो वायुमंडल में छोड़े जाते हैं।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) 1 और 2 दोनों
- (d) न तो 1 और न ही 2

उत्तर: (d)

